

संपादकीय

लंबे खिंचते चुनाव और सता में वापसी की संभावना का सारिव्यकीय सच!

चुनाव आयोग द्वारा 18 वर्षों लोकसभा के निवाचन का कार्यक्रम प्रोत्तिहासिक होने के साथ ही विषयक इस 7 चरणीय चुनाव कार्यक्रम पर सवाल उठा रहा है। संदेह का अधार यह है कि आज जब प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो गई है तब समूचे देश में गैरी हमें तब चुनाव प्रक्रिया चलाने का क्या मूलबद्ध है? 81 दिन तक आवाज सहित लगाकर विकास कार्यक्रमों पर इतने लंबे ब्रेक का क्या अंचित है? क्या इसके पाइछे किसी खास राजनीतिक दल को अपनी चुनावी किलेवंडी पुखां करने की मोहल्ले देते जाने का छुपा मंत्र है या चुनाव निष्पक्षता से कराने का अप्रयोग है? राजनीतिक हल्कों में यह सवाल भी संजीदगी से तैरने लगा है कि चुनाव प्रक्रिया के लगातार लंबा खिंचने के साथ देश क्या अंचित रूप से उस अध्यक्षीय प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, जिसमें जनता राजनीतिक दल से ज्यादा उसके चेहरे पर पर दाव लगाना ज्यादा बेहतर समझती है। प्रकारांतर से यह नए किस्से का अधिनायकवाद अथवा राजतंत्र है, जो युवता तो लोकताक्रिक प्रोसेस से है, लेकिन उसका मंत्रव्यक्ति केंद्रित सत्ता को वैधता प्रदान करना क्या आवश्यक है? क्या यह चुनावी भी विचारधारा, कार्यक्रम, प्राथमिकताओं और विकास जैसे अहम मुद्दों के परे जाकर एक चेहरे को ध्यान में रखकर ही लड़ा जा रहा है? और यह भी कि किसी चेहरे विशेष पर लोकसभास की अति निर्भाव किस सत्तातंत्र की ओर इशारा करती है? सत्ता दशकों के लोकतंत्र के बावजूद क्या भारतीय मतदाता की जड़ें अभी भी व्यक्ति अराधन से से ही सिक्क हैं। बदलाव केवल इतना है कि बंशवाद की सीमाएं लांब कर वह अब अचमकारी चेहरे पर केंद्रित हो गई है। अब पहला सवाल चुनाव प्रक्रिया के असाधारण रूप से लंबा खिंचने का, इस देश में सबसे लंबा चुनाव 1951-52 में हुआ पहला आम चुनाव था, जो लगभग 4 महीने तक 68 चरणों में हुआ था। तब देश में कुल मतदाता 17.32 करोड़ थे, जिनमें से मात्र 44.87 लोगों ने चुनावी वापसी की थी। चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था और इसमें से कांग्रेस ने 364 सीटें जीत ली थीं। विषयक कन्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी थीं, जिन्हें कुल 28 सीटें मिली थीं। चुनाव लंबा खिंचने का बड़ा कारण शायद यह था कि समूचे देश में पहली बार आम चुनाव हो रहे थे (लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे और 89 निवाचन क्षेत्रों में दोहरी जननीतिवाले प्रणाली थीं)। यानी एक ही सीट से सामान्य और आरक्षित वर्ग का प्रत्यावाची चुना था। दोनों के लिए अलग अलग मतपेटियां रखी जाती थीं। पुरे देश में 1 लाख 96 हजार से ज्यादा मतदाता दर्दी थे, इनमें से 25 लाख 527 महिलाओं के लिए आरक्षित थे। लेकिन तब भी चुनाव परिणामों, चुनाव प्रक्रिया के दोषोंवश होने तथा ऐसा करने के पाइछे किसी दल को लाभ पहुंचाने की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठे थे। तब विषयक बेहद कमज़ोर था। उस आम चुनाव में दो सूख्य विषयकी पार्टियों ने जितनी सीटें जीती थीं, उनकी संख्या आज सबसे बड़ी विषयकी पार्टी कांग्रेस के सांसदों की संख्या की तुलना में लगभग आधी थी। इसके पांच साल बाद 1957 में हुए आम चुनाव (लोकसभा के साथ साथ विस चुनाव भी) चुनाव आयोग ने मात्र 20 दिनों में सम्पन्न करा दिए। कम अवधि में चुनाव करने के बाद भी कांग्रेस ही 71 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी। यह चुनाव भी सूख्य रूप से प्रधानमंत्री पांच चरणों में जवाहरलाल नेहरू की छवि और देश के नेहरूवादी विकास मॉडल को मिला जनसमर्थन था। उन्होंने स्वरूप सरकार के सुख्य आलोचक कम्युनिस्ट और समाजवादी थे, जिनमें चुनाव में कुल 46 सीटें मिली थीं। 1962 तक आठ-आठ देश में स्वीकृत नेहरूवादी सोच की आधा घटने लगी। बेरोजगारी, अशिक्षा, महांगाह, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे सिर उठाने लगे। फिर भी कांग्रेस आम चुनाव में 361 सीटें जीतने में कामयाब रही। यह चुनाव भारत पर चीनी हमले के 8 माह पूर्व हो चुके थे। अगर चुनाव उस चीनी हमले में भारत की करारी हार के बाद हुए होते तो चुनाव परिणाम क्या होता, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। अल्बर्ट युद्ध में जीत अथवा शत्रु पर प्रत्याक्रमण सत्तावधान दल के लिए हमारा कामदंड रहे हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री पांच बारे और उनके कार्यकाल में 1965 के दौरान हुए भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना की सफलता ने कांग्रेस को सहाया दिया। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस किनारे पर ही सही, 283 सीटों के साथ वापस सत्ता में आ गई। दूसरी तरफ देश राजनीतिक करवट बदल रहा था। गैर कांग्रेसवाद की भावना जोर पकड़ने लगी थी। विषयकी पार्टियों जिनमें वामपंथी प्रमुख थे, मजबूत होने लगे थे तो दूसरी तरफ हिंदूवादी जनसंघ जैसी पार्टियों के लिए भी स्पेस बनने लगा था। धर्मनिरपेक्षता और धर्मसंपर्क के तेवर तीव्र होने लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद में टकराव तेज होने लगा था। साथ में गरीबी, महांगाह और समाजवादी सोच की अपनी राष्ट्रीयकरण उन्होंने पुराने कांग्रेसियों को दिक्कते लगाते हुए पार्टी तोड़ी और मध्यवर्ती चुनाव करवाए। इसी के साथ देश में 15 साल से चली आ रही 'एक देश, एक चुनाव' की अंचित परंपरा भी टूट गई। इंदिराजी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। देश में चुनाव फिर व्यक्ति केंद्रित हो गया। इंदिराजी की नई 'इंदिरा कांग्रेस' नए चुनाव चिह्न के साथ 352 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी। दूसरी तरफ पहली बार कम्युनिस्टों को पाइछे छोड़ते हुए विषयक में हिंदूवादी जनसंघ ने 35 सीटें जीतकर संकेत देवा कि आने वाले पांच दशकों की बाजी क्या होने वाली है। इंदिराजी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े के एरेतासिकान काम किया। इसका लाभ कांग्रेस को 1972 में राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हुआ। अधिकांश जगह कांग्रेस जीती। इसी के साथ उनमें सत्ता का घमंड भी घर कर गया। विषयक को कुचलने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। कम्युनिस्टों का एक धड़ा इस मामले में उनके साथ था इसी इमर्जेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक अदृष्टपूर्व कदम उठाते हुए भारतीय सर्विधान की उद्देशिका में सशोधन कर उसमें 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भी जुड़वा दिए। जबकि आपातकाल में समूचा विषय जेल में था। बाहरी और अंतरिक दबाव में देश में 1977 में आम चुनाव कराए गए। यह आम चुनाव प्रक्रिया महज 5 दिनों में सम्पन्न हो गई। 6 दिनों के मिलाकर बनी जनता पार्टी, जिनमें भाजपा का पूर्ववर्ती जनसंघ भी था, 295 सीटें जीतकर सत्ता में आई। उसे भारत की 'दूसरी आजादी' कहा गया। लेकिन यह आजादी ज्यादा नहीं दिक्कती। नेताओं की महत्वाकांक्षा की अंतर्कलह और राजनीतिक दिशाहीनता ने फिर से इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ किया। इंदिरा गांधी ने 1980 के चुनाव में 353 सीटें जीत कर सत्ता में वापसी की। यह चुनाव प्रक्रिया भी मात्र 2 चरणों में पूरी हो गई। जबकि बोर्टों की संख्या 1952 की तुलना में दोगुनी भी ज्यादा हो चुकी थी। चुनावी चरणों के बढ़ने के सिलसिला 1984 से तेज हुआ, जब देश में आतंकवाद बढ़ने लगा। सुरक्षा सम्बन्धी समस्या और मतदातों की बढ़ती चुनावी कारण थे। 1984 का आम चुनाव 1 महीने में 4 चरणों में हुआ। उधर विषयक के मजबूत होने से चुनाव ज्यादा कठिन, बाहुबल और धनवर्ती केंद्रित होते चले गए। चुनाव से पहले इंदिरा गांधी की हाज़ार हो गई। देश में सहानुभूति की लहर चली और कांग्रेस 414 सीटें जीत गई। (शायद इसी रिकॉर्ड की बराबरी का लक्ष्य मोदीजी ने अब एनडीए के लिए रखा है।) देश के सत्ता इंदिराजी के बेटे राजीव गांधी की हाथ आई। वो परिस्थितिवश पोर्टफोली थे। बहुत ज्यादा राजनीतिक व जमानी संघर्ष का अनुभव और सियासी चुतुर्गी उभयों थी। 1989 चुनाव वो कांग्रेस को नहीं जितवा सके। उधर बोर्टों का प्रार्थिक और जातीय आधार पर धर्वाकरण और तेज हो गया। +

परिवार से रिश्ता पुराना है, प्रासांगिकता के लिए संघर्ष कर रही नेहरू-गांधी की थकी हुई विरासत

परिवार मायने रखता है। एक बुनियादी सामाजिक इकाई के रूप में परिवार राजनीति में विचारधारा को स्थायित्व की भावना देता है, जबकि सिद्धांत केवल निश्चितता प्रदान करते हैं। एक ऐसे युग में, जब दृश्य एवं अचूंचे संवेदन संबंधी चुनाव अभियान में लोगों की धारणाओं को प्रभावित करते हैं, हर कोई अपनी आदर्श परिवारिक तत्वीर को भुनाना चाहता है। यह उन समाजों में अधिक होता है, जहाँ राजनीति में सार्वजनिक एवं निजी, दोनों तरफ खुले-मिले होते हैं। राजनीति में सत्ता विरासत के रूप में परिवार से भी मिलती है। प्रतिभा और लोकप्रियता से यादा रक्षण एवं उत्तम भजन बन जाता है। यह उन परिवारों में होता है, जहाँ भरोसे का सबसे सच्चाई स्वरूप लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विरुद्ध विकास और संरक्षण के लिए एक तरफ सत्ता को स्वतंत्रता का, और अगर कोई एक सर्विधानेतर संस्था है, जिसने लोकतंत्र के रूप में राष्ट्र की आवाज को परिवारित किया है, तो वह परिवार है। नेहरू-गांधी परिवार भले ही लोहा रहे हैं, उन्होंने एक तरफ देश के सबसे स्थायी परिवारों में दोहरी जननीतिवाले प्रणाली थीं। यानी एक ही सीट से आम चुनाव के लिए लगभग एक तरफ एक तरफ आवश्यक है। यह उन परिवारों में होता है, जहाँ भरोसे का सबसे सच्चाई स्वरूप लोकतंत्र की विविधता के विरुद्ध विकास और संरक्षण के लिए एक तरफ सत्ता को स्वतंत्रता का और अगर कोई एक सर्विधानेतर संस्था है, जिसने लोकतंत्र के रूप में राष्ट्र की आवाज को परिवारित किया है, तो वह परिवार है। नेहरू-गांधी परिवार के लिए एक तरफ सत्ता को स्वतंत्रता का, और अगर कोई एक सर्विधानेतर संस्था है, जिसने लोकतंत्र के रूप में राष्ट्र की आवाज को परिवारित किया है, तो वह परिवार है। नेहरू-गांधी परिवार के लिए एक तरफ सत्ता को स्वतंत्रता का, और अगर कोई एक सर्विधानेतर संस्था है, जिसने लोकतंत्र के रूप में राष्ट्र की आवाज

आंध प्रदेश और केरल में सबसे महंगा है पेट्रोल

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन टिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन टिमिटेड (एचपीसीएल) ने पिछले सप्ताह ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इससे पहले करीब दो साल से बाहन इंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस कटौती से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन वैट को ऊंची दरों की वजह से कई राज्यों में अब भी बाहन इंधन 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक है। देश में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा है। वहीं जिन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों 107.39 रुपये प्रति लीटर है। डीजल कीमतों की बात की जाए, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में यह इंधन 97.6 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इसके बाद केरल की राजधानी विवरनंपुरम में यह 96.41 रुपये प्रति लीटर, हैदराबाद में 95.63 रुपये और रायपुर में 93.31 रुपये प्रति लीटर है।

भाजपा शासित राज्यों में ऐसी है स्थिति बीजेपी शासित राज्य भी पीछे नहीं हैं, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106.45 रुपये प्रति लीटर, पटना में 105.16 रुपये (यहां भाजपा जदू राजकार के साथ गठबंधन में है), जयपुर में 109.87 रुपये प्रति लीटर है। इसके बाद लेफ्ट डेमोक्रेटिक



फंट (एलडीएफ) शासित केरल का नंबर आता है। वहां एक लीटर पेट्रोल 107.54 रुपये में बिक रहा है। कांग्रेस शासित तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत 103.93 रुपये प्रति लीटर है। अंकड़ों के अनुसार, जिन अन्य राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक है तो उनमें आडिशा (भुवनेश्वर में 101.04 रुपये प्रति लीटर), तमिलनाडु (चेन्नई में 100.73 रुपये) और छत्तीसगढ़ (रायपुर में 100.37 रुपये) शामिल हैं। भाजपा शासित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार में डीजल का दाम 92 से 93 रुपये प्रति लीटर है। इंधन कीमतों में कटौती पर गोल्डमैन सैक्षण्य ने कहा कि तीनों पेट्रोलियम कंपनियों विपणन कंपनियों का शुद्ध विपणन मार्जिन 1.7-2.7 रुपये प्रति लीटर से घटकर 80-90 पैसे प्रति लीटर रह जाएगा।

सिलवासा और दमन हैं जहां यह 92.38-92.49 रुपये प्रति लीटर है। अन्य छोटे राज्यों में भी पेट्रोल सस्ता है। इनमें दिल्ली (94.76 रुपये प्रति लीटर), पाण्डी (95.19 रुपये), आहाजोल (93.68 रुपये) और गुवाहाटी (96.12 रुपये) शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वाप्र में डीजल सबसे सस्ता है जहां यह लगभग 78 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। महानगरों में दिल्ली में बैट सबसे कम है। दिल्ली में डीजल 87.66 रुपये प्रति लीटर है, जबकि गोवा में इच्छी कीमत 87.76 रुपये प्रति लीटर है। इंधन कीमतों में कटौती पर गोल्डमैन सैक्षण्य ने कहा कि तीनों पेट्रोलियम कंपनियों विपणन मार्जिन 1.7-2.7 रुपये प्रति लीटर से घटकर 80-90 पैसे प्रति लीटर रह जाएगा।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी इन्वेस्टमेंट कर रही कंपनी

650 करोड़ खर्च कर मदर डेयरी बनाएगी दो नए प्रोसेसिंग प्लांट



नई दिल्ली। दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (टुकड़े) में प्रमुख दूध सप्लायर मदर डेयरी दो और नए प्लांट्स बनाने के लिए करीब 650 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी इससे बढ़कर मार्केट डिमांड को पूरा करेगी। इसके अलावा मदर डेयरी अपनी मौजूदा प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ और इन्वेस्ट करेगी। न्यूज एजेंसी ढक्क ने इस बात की जानकारी दी है। मदर डेयरी फ्लॉट्स एंड वेजिटेल्स प्रावेंटर लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष बंदलिशन ने कहा, हाँ हम अपने डिव्हील्यूएन नेटवर्क और कर्स्टमर्स तक पहुंच बढ़ाने के लिए अपने प्रमुख जगहों पर अपनी डेयरी और (फल-

सविजया) प्रोसेसिंग कैमेसिटी के विस्तार के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। नगापुर में 525 करोड़ की लाख लाख लीटर डूध की प्रोसेसिंग होगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 लाख लीटर करिए। यह प्लांट देश के साउथर्न रीजन में सर्विस प्रोवाइडर। कंपनी अपने ब्रांड को कनाटक में भी बढ़ा रही है। स्टेट में मदर डेयरी एक नया फ्लॉट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने की भी प्लानिंग कर रही है। कंपनी इसमें 125 करोड़ खर्च करेगी। नागपुर और कर्नाटक के ये दोनों प्लांट अगले 2 साल में पूरा हो जाएंगे।

मदर डेयरी के पास फिलहाल 9 प्रोसेसिंग प्लांट्स में सबसे बड़ा डेयरी के पास फिलहाल 9 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। जिसकी डेली कैपेसिटी 50 लाख लीटर से ज्यादा है। कंपनी थर्ड-पार्टी प्लांट्स में भी प्रोसेसिंग करती है।

सविजया प्रोसेसिंग कैमेसिटी ने एक बड़ा डेयरी ब्लॉप्ट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष बंदलिशन ने कहा, हाँ हम अपने डिव्हील्यूएन नेटवर्क और कर्स्टमर्स तक पहुंच बढ़ाने के लिए अपने प्रमुख जगहों पर अपनी डेयरी और इन्वेस्टमेंट से महाराष्ट्र के नागपुर

में एक बड़ा डेयरी प्लांट लगा रही है। इस प्लांट में रोजाना 6 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 लाख लीटर करिए। यह प्लांट देश के साउथर्न रीजन में सर्विस प्रोवाइडर। कंपनी अपने ब्रांड को कनाटक में भी बढ़ा रही है। स्टेट में मदर डेयरी एक नया फ्लॉट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने की भी प्लानिंग कर रही है। कंपनी इसमें 125 करोड़ खर्च करेगी। नागपुर और कर्नाटक के ये दोनों प्लांट अगले 2 साल में पूरा हो जाएंगे।

मदर डेयरी के पास फिलहाल 9 प्रोसेसिंग प्लांट्स में सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कंपनी पिल्लालू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (टुकड़े) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी

करती है।

2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए-वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के मुताबिक, मौजूद वित्त वर्ष (2023-24) में कंपनी का ओवरऑल प्रोथ्र 7 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। मदर डेयरी की स्थाना 1974 में हाँ अपरेशन फ्लॉट्स इनशिएटिव के तहत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कंपनी पिल्लालू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (टुकड़े) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी

करती है।

2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए-वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के मुताबिक, मौजूद वित्त वर्ष (2023-24) में कंपनी का ओवरऑल प्रोथ्र 7 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। मदर डेयरी की स्थाना 1974 में हाँ अपरेशन फ्लॉट्स इनशिएटिव के तहत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कंपनी पिल्लालू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (टुकड़े) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी

करती है।

2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए-वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के मुताबिक, मौजूद वित्त वर्ष (2023-24) में कंपनी का ओवरऑल प्रोथ्र 7 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। मदर डेयरी की स्थाना 1974 में हाँ अपरेशन फ्लॉट्स इनशिएटिव के तहत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कंपनी पिल्लालू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (टुकड़े) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी

करती है।

2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए-वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के मुताबिक, मौजूद वित्त वर्ष (2023-24) में कंपनी का ओवरऑल प्रोथ्र 7 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। मदर डेयरी की स्थाना 1974 में हाँ अपरेशन फ्लॉट्स इनशिएटिव के तहत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कंपनी पिल्लालू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (टुकड़े) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी

करती है।

2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए-वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के मुताबिक, मौजूद वित्त वर्ष (2023-24) में कंपनी का ओवरऑल प्रोथ्र 7 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। मदर डेयरी की स्थाना 1974 में हाँ अपरेशन फ्लॉट्स इनशिएटिव के तहत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कंपनी पिल्लालू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (टुकड़े) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी

करती है।

2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए-वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के मुताबिक, मौजूद वित्त वर्ष (2023-24) में कंपनी का ओवरऑल प्रोथ्र 7 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। मदर डेयरी की स्थाना 1974 में हाँ अपरेशन फ्लॉट्स इनशिएटिव के तहत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कंपनी पिल्लालू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (टुकड़े) की फुली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी

खरगोन के भीकनगाँव में शराब दुकान के बाहर खुलेआम छलक रहे जाम

गाँव गाँव परेसी जा रही शराब, खुल के उड़ रही पुलिस व अबाकारी के नियमों की धज्जियां

पिंपूष अग्रवाल। सिटी चीफ खरगोन, भीकनगांव मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 1 अप्रैल 2023 से ही मध्यप्रदेश के अदाते बन्द कर दी गई लेकिन भीकनगांव शहर में रित शराब दुकान पर ठेकेदार द्वारा खुल कर अबाकारी व प्रशासन के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रदेश में शराब दुकान के पास चलने वाले आहते बंद हो गए, लेकिन पीने वालों की भीड़ कम नहीं हुई। सुबह हो दोर या शाम शराब की दुकान के आसपास खुले में ही जाए छलकने लगते हैं। शराब की दुकान के बाहर शाम ठेते ही भीड़ जमा हो जाती है। देवी-विदेशी शराब के शोकीन दुकान के आसपास ही टेलों से पीने की सामग्री लेकर खड़े नजर आते हैं।

स्थानीय अबाकारी और पुलिस की नजर नहीं या मिलीभगत- ऐसा नहीं है कि खुले में दुकान के सामने छलक रहे जाम पर अबाकारी और पुलिस की नजर नहीं है। शराब दुकानों के सामने से पुलिस और अबाकारी अधिकारी भी उन तक नजर नहीं पड़ी अब देखना यह होगा कि भीकनगांव का स्थानीय



